हिन्दी मासिक पत्रिका

मूल्य ₹50/-

तेजस बिन्दु

वर्ष-02, अंक-01, अगस्त-2024

RNI No.: UPHIN/2023/87359

भ्रष्टाचार की साझेदारी ?

मुलायम आर्मी
भारत एकता मिशन
स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाएं
संस्थापक
लालजी यादव
(राष्ट्रीय सचिव मुलायम आर्मी)
भारत एकता मिशन

RNI No.: UPHIN/2023/87359

तेजस बिन्दु

हिन्दी मासिक पत्रिका मूल्य : ₹50/-

वर्ष:02, अंक-01, अगस्त-2024

संपादक
आरती यादव

सह संपादक
निशा सिंह

प्रबन्ध संपादक
दुर्गावती देवी

विधिक सलाहकार
मानती यादव

संवाददाता
साधना देवी, गीता देवी

मैगजीन लेआउट
पूजा यादव
8881544447

तेजस बिन्दु के लिए स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, आरती यादव द्वारा इशिता प्रिन्टर्स, 168/8, हेवेट रोड़, हुसैनगंज चौराहा, लखनऊ (उ०प्र०)–226001 से मुद्रित एवं 251 ग्रा० लटेरा पो०–धोरहरा डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)–272189 से प्रकाशित।

रजिस्टर्ड कार्यालय
251 ग्रा० लटेरा पो०-धोरहरा डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)-272189

Mob. 9838595489
E-mail:tejasips89@gmail.com

पत्रिका से संबंधित समस्त वाद विवादों का न्याय क्षेत्र सिद्धार्थनगर, उ०प्र० न्यायालय होगा।

सभी पद अवैतनिक है।

इस अंक में

20 भ्रष्टाचार की साझेदारी ?

06 कारगिल विजय दिवस

09 अमर शहीद कंचन यादव की प्रतिमा का अनावरण

13 भारत में ओबीसी...

16 बहुजन पहचान पर प्रश्न चिन्ह

अपना प्रधानमंत्री कितना झूठा कितना सच्चा?

हम भारतवासी बहुत गर्व से बोलते है हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये पूरी तरह से सच भी है। सबसे बड़ा लोकतंत्र का मतलब है की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हमने एक मजबूत लोकतंत्र खड़ा किया था।लोकतंत्र बनता है जनता के विश्वास से जब जनता को सिस्टम पर भरोसा हो, अपने सबसे बड़े नेता पर भरोसा हो,ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब देश के प्रधानमंत्री पर बात आए तो। लोकतंत्र का रक्षा प्रधानमंत्री की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को लोगों मे विश्वास लाना होता है,प्रधानमंत्री को देश के नागरिकों का सम्मान करते हुए लोगों से ऐसा कुछ झूठ नही बोलना चाहिए जिससे की लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाए। अगर बात करें वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तो झूठ बोलने या वरगलाने का सिलशिला शुरू किया 2014 से पहले जब भारत मे आम चुनाव होने थे, इन्होंने भी वादों की लाइन लगा दी, अब जनता उस समय कांग्रेस सरकार से उब चुकी थी तो, जनता नरेंद्र मोदी के बहकावे मे आसानी से आ गयी। इन्होंने जो भी झूठे वादों के सपने दिखाए जनता ने आँख बंद कर के भरोसा कर लिया।

जैसे ब्लैक मनी वापस लाकर सबके खाते मे 15-15 लाख, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां, पेट्रोल और डिजल के दाम आधे कर देना वैसे ही बहत सारी दिखावटी स्कीम जैसे की स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया आदि जो सिर्फ काग़ज़ पर दिखते है। ऐसे ही झुठ का सिलसिला 2019 आम चुनाव मे दिखा है जैसे किसानो की आय दोगुनी कर देना,किसानो को पेंशन, दुकानदारों को पेंसन,समान नागरिक संहिता, स्मार्ट सिटी, कई शहरों मे मेट्रो जैसे सुविधा आदि ऐसे झूठे वादों की एक लंबी सूची है। और ये सभी वादे नरेंद्र मोदी ने खुद किए। नरेंद्र मोदी को ये समझना होगा की ऐसे झूठ बोलने से लोगों का विश्वास कम होता है देश के नेताओं पर,देश के सिस्टम पर।

जितने झूठ नरेंद्र मोदी ने बोले है शायद इस देश के इतिहास मे किसी नेता ने प्रधानमंत्री जैसे औंधे पर बैठकर झूठ नही बोला होगा। भारत के इतिहास का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है।लेकिन वही अब लोगों को भी धीरे धीरे झूठ समझ मे आ रहा है और इसका प्रभाव देखा जा सकता है, देर से ही सही पर लोगों ने इनके वादों, इनके फ़र्ज़ी स्कीम पर भरोसा करना बंद कर दिया है और एक नए विकल्प के प्रयास मे है। जितना जल्दी इस देश की जनता समझ जाएगी उतना जल्दी इस देश को इस झूठे प्रधानमंत्री से छुटकारा मिल जाएगा, और देश को वापस प्रगति पर ला पाएंगे।

सम्पादक

आरती

विदाई समारोह का आयोजन कमांडर विजेंद्र सिंह यादव को दी गई भावभीनी विदाई, जताया आभार

नये ई सी एच एस प्रभारी कर्नल यासीन का स्वागत सम्मान समारोह

ब्यूरो डेस्क

फिरोजाबाद सैनिक समाज सेवा संगठन इकाई फिरोजाबाद द्वारा कमांडर बिजेंद्र सिंह यादव प्रभारी ईसीएचएस फिरोजाबाद का विदाई समारोह एवं नवागत प्रभारी कर्नल यासीन का स्वागत समारोह मेजर रामबीर सिंह आई टी आई कॉलेज आवास विकास कालोनी शिकोहाबाद में अध्यक्ष विशेष कुमार यादव के

फिरोजाबाद का विदाई समारोह एवं नवागत प्रभारी कर्नल यासीन का स्वागत समारोह मेजर रामबीर सिंह आई टी आई कॉलेज आवास विकास कालोनी शिकोहाबाद में अध्यक्ष विशेष कुमार यादव के कुशल नेतृत्व में सभी सम्मानित पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया।

कुशल नेतृत्व में सभी सम्मानित पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत दोनों अधिकारियों के परिचय स्वागत सत्कार के साथ कराया गया इस दौरान कमांडर बिजेंद्र सिंह व कर्नल यासीन ने अपने अपने विचार व्यक्त किए संरक्षक इंजीनियर रामब्रेस यादव द्वारा कमांडर बिजेंद्र सिंह के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और दोनों अधिकारियों ने पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण किया गया स्कूल के बच्चो ने नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया और सभी का अभिवादन किया इस दौरान दोनों अधिकारियों को संगठन की ओर से संगठन का प्रतीक चिन्ह भेंट कर फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया अन्त में जलपान के बाद एक दूसरे के गले मिलकर भारत माता के नारे लगाए गए।

इस अवसर पर मौजूद रहे संरक्षक इंजीनियर रामब्रेस यादव, मण्डल अध्यक्ष रविन्द्र कुमार यादव, अध्यक्ष विशेष कुमार यादव, उपाध्यक्ष दलबीर सिंह यादव, सचिव प्रयाग चन्द्र यादव, कोसा अध्यक्ष ध्रुव जीत सिंह, मीडिया प्रभारी मुरारी लाल, शिकोहाबाद तहसील अध्यक्ष केके शर्मा, सिरसागंज तहसील अध्यक्ष एमपी सिंह यादव, जसराना तहसील अध्यक्ष रवीश कुमार यादव, अनवर सिंह, ज्ञानीराम, विरेंद्र सिंह, रामबीर सिंह, दिनेश चंद्र यादव आदि मौजूद रहे।

कारगिल विजय दिवस

ब्यूरो डेस्क

आज से ठीक 25 साल पहले के उन दिनों को याद कर देश उन वीरों के समक्ष नतमस्तक है जिन्होंने मां भारती की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज के ही दिन हमारी सेना ने अपने अदम्य साहस और वीरता के बल पर पाकिस्तानी सेना को धूल चटायी थी। सन् 1999 में कारगिल की गगनचुंबी पहाड़ियों और माइनस जीरो डिग्री के नीचे तापमान में हमारे देश के रण बाकुरों ने जो युद्ध लड़ा, वह युद्ध आपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। वैसे यह युद्ध कारगिल युद्ध,के नाम से ज्यादा जाना जाता है। कारगिल जम्मू और कश्मीर का एक जिला है जो कि वर्तमान समय में लद्दाख का भाग है। जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 814 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया है। यह नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों राजौरी, पुंछ, उड़ी, कारगिल और लेह होते हुए सियाचिन तक जाती है। इस नियंत्रण रेखा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए है जो कि श्रीनगर, कारगिल, द्रास और लेह को जोड़ता है। इस राजमार्ग के बंद होते ही लेह का संबंध देश से टूट जाता है। इन क्षेत्रों में 6000 फीट से 17000 फीट तक की ऊंचाई वाले पहाड़ है, जिन पर पूरे वर्ष 20 से 30 फीट तक मोटी बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र में 15000 फीट तक गहरी खाईयां, दूर दूर तक फैली कटीली झाड़ियां तथा संकरे और दुर्गम मार्ग हैं। इन क्षेत्रों में पूरे वर्ष बर्फ जमीं रहती है , सितंबर अक्टूबर में तापमान शून्य से भी नीचे पहुंच जाता है। पाकिस्तान की प्रवृत्ति हमेशा धोखे की रही है। वह जानता है कि घोषणा करके युद्ध लड़ना उसके बस की बात नहीं है। उसने 1947 तथा 1965 के दोनों युध्दों में भी शुरू में अपने नियमित सैनिकों को कबीलाई कहता रहा है। वह इस बार भी अपने नियमित सैनिकों को मुजाहिदीन कहता रहा। कारगिल का यह युध्द पिछले बीस सालों से चले आ रहे जिहादियों की नीति के पोषक पाकिस्तान तथा उसकी दबी इच्छाओं का अभियान था। यह अनेक मामलों में पहले की दोनों लड़ाइयों से भिन्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में 03 मई से 26 जुलाई तक कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए भीषण युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध वही लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तानी सेना ने द्रास, कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह परास्त किया था। 03 मई 1999 को एक चरवाहे ने बटालिक सेक्टर की पहाड़ियों में कुछ पाकिस्तानी लोगों को देखा। उसे पहाड़ियों के ऊपर कुछ गड़बड़ लगी। उसने वहां से वापस जाकर इसकी सूचना भारतीय सेना की 3 पंजाब रेजिमेंट को दी। इस सूचना की पुष्टि के लिए 3 पंजाब रेजिमेंट के कुछ जवान उस चरवाहे के साथ बतायी हुई जगह पर गये। उन्होंने टेलीस्कोप से काफी छानबीन की। भारतीय सैनिकों ने देखा कि पहाड़ियों पर कुछ लोग घूमते हुए दिखायी पड़ रहे हैं। सैनिकों ने वापस जाकर इस घटना की खबर अपने उच्च अधिकारियों को दी। इस खबर को सुनकर सेना हरकत में आ गयी। लगभग दो बजे एक हेलीकाप्टर से उन पहाड़ियों पर नजर दौड़ाई गयी, तब जाकर पता चला कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है। घुसपैठियों के वेष में धोखेबाज पाकिस्तानी सैनिक कारगिल स्थित द्रास, मश्कोह, बटालिक आदि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना ठिकाना बनाकर पूरी सामरिक तैयारी के साथ आक्रमण के उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी क्रम में 05 मई को स्थिति का जायजा लेने के लिए एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गयी। जिसे पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया और उनमें से

05 सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी। 3 पंजाब ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी और 7 मई 1999 तक घुसपैठ की पुष्टि हो गयी। 3 इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्यालय ने तत्काल कारवाई शुरू कर दी। 10 मई 1999 तक बटालिक सेक्टर में और दो बटालियनों को तैनात कर दिया गया। इस क्षेत्र में अभियान की कमान संभालने के लिए 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड का मुख्यालय बटालिक में स्थापित कर दिया गया। 09 मई को पाकिस्तानी हमले में कारगिल में स्थित आयुध भंडार नष्ट हो गया। 10 मई को पता चला कि द्रास, मश्कोह और काकसर में भी पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की है। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गयी। इस बात की भी पुष्टि हो गयी कि दुश्मन तुरतुक सेक्टर में नियन्त्रण रेखा और उसके दूसरी ओर भी मोर्चा संभाल चुका है। 18-31 मई के बीच चोर बाटला सेक्टर में कुछ ओर सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी गयीं और इस क्षेत्र में दुश्मन के घुसपैठ के प्रयासों को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। कारगिल में जो कुछ देखने को मिल रहा था उससे पता चल गया कि वह अपने नियमित सेना का प्रयोग करके हमारी जमीन पर कब्जा करने की सोची समझी योजना का हिस्सा है। यह भी स्पष्ट था कि जिन चोटियों पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था उन्हें खाली कराने के लिए संसाधन और अच्छी तैयारी की आवश्यकता होगी। शुरूआाती दिनों में दुश्मन को भगाने के जो प्रयास किये गये, उनमें काफी संख्या में हमारे सैनिक हताहत हुए क्योंकि दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर बैठा हुआ था। जहां से हमारी हर गतिविधि दिखाई पड़ती थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 26 मई को भारतीय वायुसेना को भी इस अभियान में शामिल कर लिया गया। भारतीय वायु सेना ने "सफेद सागर" नाम से अपना अभियान शुरू किया। शुरूआती दौर में हमारी वायुसेना को भी क्षति उठानी पड़ी लेकिन बाद में उसने अपनी रणनीति में सुधार किया। वायुसेना ने आगे के अभियान के लिए थलसेना को अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई। वायु सेना के माध्यम से दुश्मन की शक्ति और उसकी तैनाती के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई। रैकी से पता चला कि बटालिक, कारगिल, द्रास और मश्कोह सेक्टरों में दुश्मन की एक एक एक ब्रिगेड तैनात थी। प्रत्येक ब्रिगेड में शुरू में पाकिस्तान की नार्दन लाइट इन्फेंट्री की 02 बटालियनें, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की 02 कम्पनियां और फ्रंटियर कोर के लगभग 600-700 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्रिगेड में लगभग 02 तोपखाना की यूनिटें, इंजीनियर, सिग्नल और प्रशासनिक इकाईयां शामिल थीं। आरम्भ में दुश्मन से उन क्षेत्रों को खाली कराने की योजना थी, जहां से वे राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए पर अपना अधिकार जमाए हुए थे और उसके बाद अन्य क्षेत्रों से दुश्मन को खदेड़ने की योजना थी। राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियन्त्रण रेखा के उस पार न जाने का निर्णय लिया गया। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले द्रास सेक्टर, मश्कोह घाटी, बटालिक सेक्टर और फिर काकसर सेक्टर को सुरक्षित करने की योजना बनाई गयी। 8 माऊंटेन डिवीजन को कारगिल, द्रास और मश्कोह सेक्टरों से पाकिस्तानियों को भगाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। उसके नियन्त्रण में तीन माऊंटेन ब्रिगेड थी। 3 इन्फेंट्री डिवीजन बटालिक और तुरतुक के क्षेत्रों के अभियान की जिम्मेदारी सम्भाले हुए थी। एक माऊंटेन ब्रिगेड को बटालिक सेक्टर के अभियान की कमान संभालने के लिए पहले ही रवाना कर दिया गया था। द्रास - मश्कोह सेक्टर में सबसे पहले तोलोलिंग पर कब्जा करने की योजना थी। द्रास में 18 ग्रिनेडियर्स तोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए तीन प्रयास पहले ही कर चुकी थी। 02 जून को 18 ग्रिनेडियर्स ने तोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए अपना चौथा प्रयास किया। भारी प्रतिरोध का सामना करते हुए वह 10 जून तक ऐसे स्थान पर पहुंच गयी जो पाकिस्तानी पोजीशन से लगभग 30 मीटर नीचे था। 2 राजपूताना राइफल्स ने 12 जून को तोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए उस स्थान को एक मजबूत आधार के रूप में प्रयोग किया। 12 जून को रात 11 बजे उसने हमला

शुरू किया और घमासान लड़ाई के बाद प्वाइंट 4590 पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 ग्रिनेडियर्स ने 12 राजपूतना राइफल्स के साथ आगे बढकर प्वाइंट 4590 से 03 किमी आगे पोजीशन पर कब्जा कर लिया। बाद में प्वाइंट 5140 पर हमला करने के लिए इसी प्वाइंट 4590 का प्रयोग किया गया। प्वाइंट 5140 पर कब्जा करने के लिए 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स ने दो बार प्रयास किये लेकिन उसे ज्यादा सफलता नही मिली थी। 19 जून को 18 गढवाल राइफल्स, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स और 1 नागा ने एक साथ मिलकर हमला किया। अंततोगत्वा 20 जून को रात 3:35 बजे तक पोजीशन पर कब्जा कर लिया गया। 29 जून को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के पास की दो पोस्ट 5060 व 5100 पर फिर से तिरंगा लहराया। यह पोस्ट हमारी सेना के नजरिए से महत्वपूर्ण थी इसीलिए इसे जल्दी कब्जा किया गया। 02 जुलाई के दिन भारतीय सेना के जवानों ने कारगिल को तीन तरफ से घेर लिया। दोनों देशों की तरफ से खूब गोलीबारी हुई। अंततः टाइगर हिल पर हमारी सेना ने तिरंगा लहराया। हमारी सेना ने धीरे धीरे सभी पोस्टों पर कब्जा जमा लिया। 26 जुलाई को आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध को समाप्त घोषित कर दिया गया । अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में हमारे देश के कुल 674 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 1363 घायल हुए जबकि पाकिस्तान के 1200 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे । इस युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए देश के बहादुर सैनिकों को 04 परमवीर चक्र ,10 महावीर चक्र और 70 वीर चक्र प्रदान किए गए हैं। इस युद्ध में उत्तर प्रदेश के 103 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और उन्हें उनकी वीरता के लिए 02 परमवीर चक्र तथा 01 महावीर चक्र प्रदान किया गया । इस युद्ध में 17 यूनिटों को उनकी बहादुरी के लिए चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन प्रदान किया गया । इस युद्ध में भारतीय तोपखाना की तोपों ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी। बोफोर्स , 130 एम एम , 105 एम एम की तोपों ने हमारी पैदल सेना को बहुत ही श्रेष्ठ और अचूक कवरिंग फायर प्रदान किया था । इनकी कवरिंग फायर के बिना पाकिस्तानी सेना को गगनचुम्बी चोटियों से खदेड़ना मुश्किल था । इस युद्ध में सेना वायु रक्षा कोर की यूनिटों ने पूरे युद्ध क्षेत्र को अभेद्य हवाई सुरक्षा प्रदान की थी । इन यूनिटों की निगहबानी के कारण पाकिस्तान हवाई हमलों की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि वह 1971 के युद्ध में अपने युद्धक विमानों और वायु सेना के फाइटर पायलट का हश्र देख चुका था । 1971 के युद्ध में सेना वायु रक्षा कोर (तब तोपखाना) के तोपचियों ने पाकिस्तानी युद्धक विमानों के परखच्चे उडा दिए थे । कारगिल की दुर्गम चोटियों पर लड़ें गये इस युद्ध में हमने अपने बहुत से बहादुर जवानों को खोया है। विजय दिवस आते ही उन परिवारों के दुख पुनः हरे हो जाते हैं । हम सब का कर्तव्य है कि हम उन वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिजनों की हर संभव मदद करें, उन्हें सम्मान दें ताकि वह परिवार स्वयं को अकेला महसूस न करें। सरकार और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उच्च पदों पर बैठे लोग उस समय वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिजनों से किया गया वादा भूल चुके हैं। कारगिल ही क्या अब तक सेना द्वारा लड़ें गये अन्य युद्धों के वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिजनों का कमोबेश यही हाल है। केवल दिवस मनाने, अमर रहें के नारे लगाने या वीरगति प्राप्त सैनिकों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ा देने से हमारे कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो जाता। हमारे देश के वीरों ने सैनिक बनने के समय देश से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है, अब बारी देश, समाज और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की है कि वह बिना किंतु परंतु किए हुए वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिजनों की देखरेख करें और उन्हें सम्मान दें।

(इन पंक्तियों का लेखक द्रास और कारगिल में इस युद्ध में लड़ चुका है।)

अमर शहीद कंचन यादव की प्रतिमा का अनावरण

सैनिक समाज सेवा संगठन के तत्वाधान में भव्य अनावरण कार्यक्रम में उमड़े हजारों के जनसैलाब ने भावुक होकर शहीद सैनिक को किया याद शहीद सैनिकों के परिजनों के सम्मान को प्रयासरत अध्यक्ष जयसिंह के सराहनीय योगदान की सराहना

ब्यूरो डेस्क

जिले के ऊंचाहार में अमर शहीद कंचन यादव की भव्य प्रतिमा का अनावरण उनके परिजनों द्वारा किया गया। सैनिक समाज सेवा संगठन के तत्वाधान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़ ने संदेश दिया कि कंचन को युगों युगों तक याद किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में उनके परिजनों को सम्मानित किया गया । वीर रस से ओतप्रोत आल्हा ने मौजूद आमजन को सैनिक की शहादत याद करने को मजबूर कर दिया ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेना कर्नल सौरभ सक्सेना, विशिष्ट अतिथि प्रबंधक न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक महाविद्यालय शशिकांत शर्मा, प्रबंधक पंचशील महाविद्यालय बीएन मौर्य रहे। कार्यक्रम में बाबा रामकुमार दास इंटर कालेज खरौली के बच्चों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को यादगार बनाया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएन यादव ने की।

इस मौके पर **नायब सूबेदार कृष्ण मुरारी, हवलदार एसबी सिंह, लांस नायक सुमित कुमार, पूर्व कानूनगो रामस्वरूप यादव, निरंजन निषाद, डा रमेशचंद्र चौरसिया, राम जियावन यादव, रामनरेश यादव, शिवहर्ष यादव, शिव बहादुर यादव, राम अभिलाष, प्रधान गंगा विष्णु यादव, प्रधान पप्पू यादव, प्रधान राजू यादव, पूर्व प्रधान दीपक निषाद, गिरधारी यादव, शिवप्रसाद यादव, सदाशिव यादव, महाराजदीन, बृजलाल मौर्य उंचाहार अध्यक्ष घनश्याम शुक्ला, फौजी हरिकिशन मौर्य, फौजी दूधनाथ पाल, रामशंकर यादव, सैनिक समाज सेवा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फौजी राज मोहन, राष्ट्रीय महासचिव, फौजी राजेश कुमार, जिलाध्यक्ष फौजी रामबहादुर यादव, महिला ज़िलाध्यक्ष सुभाषिनी सिंह, फौजी अनिल कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन कुमार विलियम, सोनू यादव मंडल अध्यक्ष, फौजी देश कुमार, फौजी श्री राम मौर्य, फौजी सत्येंद्र यादव, फौजी संतराम यादव, फौजी अवधेश कुमार, जिला सचिव अंबेश चौधरी अशोक यादव, जितेंद्र यादव, सहित हजारों लोग मौजूद रहे।** यह जानकारी देते हुए मुख्य संरक्षक फौजी प्रेमचंद यादव और सैनिक समाज सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी जयसिंह यादव एडवोकेट ने बताया कि ग्राम पूरे चक मजरे खरौली में अमर शहीद सैनिक की प्रतिमा का अनावरण उनके परिजनों द्वारा ऐतिहासिक तरीके से कराने को पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी चल रही थी। उन्होंने सभी आगन्तुको का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिले की होनहार बेटी आंशी यादव ने उपलब्धि अर्जित कर समाज का बढ़ाया मान

स्थापना दिवस पर परिजनों को सम्मानित करेगा सैनिक समाज सेवा संगठन

"होनहार बिरवान के होत चिकने पात" उक्त मुहावरा एक सेवानिवृत्त सैनिक के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। उल्लेखनीय है कि डलमऊ क्षेत्र के बनापार के दुर्गापुर निवासी शिवशंकर यादव की होनहार पुत्री आंशी यादव ने राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में स्थान प्राप्त करके परिवार का नाम रोशन किया है। बताते चलें कि न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली के मेरेन्डा हॉउस कालेज से साईटिस्ट की तैयारी करते हुए आंशी यादव का चयन एनडीए में हुआ है। इस उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए सैनिक समाज सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयसिंह यादव फौजी ने कहा कि एक सैनिक परिवार को इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है कि उसके बाद उसके परिवार की अगली पीढ़ी भी राष्ट्र की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एनडीए की एकमात्र सीट पर आंशी यादव का चयन होना ऐतिहासिक रूप से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है जो सदैव याद किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि सैनिकों के परिवार के होनहार बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरसंभव मदद करने के लिए सैनिक समाज सेवा संगठन परिवार हमेशा तत्पर रहेगा। सैनिक समाज सेवा संगठन अपने आगामी स्थापना दिवस पर परिजनों को सम्मानित करेगा।

हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव और एकता की नई भावना को बढ़ावा देना चाहता है-कन्हैया पासवान

(रामू गौड़ ब्यूरो चीफ)

सिद्धार्थनगर- भारतीय जनता पार्टी शोहरतगढ विधानसभा का हर घर तिरंगा कार्यक्रम अभियान को सफल बनाने के लिए रविवार को सुबह 10:00 सरदार भगत सिंह चौक चिल्हिया से तिरंगे झंडे के साथ सैकड़ों की संख्या में बाईक रैली निकाली गयी। तथा रैली का समापन शोहरतगढ नगर पंचायत स्थित भारत माता चौक पर किया गया। इस रैली के मुख्य अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष लालजी त्रिपाठी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप क्षेत्रीय विधायक विनय वर्मा रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा

कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव और एकता की नई भावना को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों में तिरंगा फहराने और झंडे के साथ एक सेल्फी क्लिक कर इसे harghartiranga.com पर अपलोड करने का आग्रह किया है। यह अभियान 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू किया था। कार्यक्रम के संयोजक विधानसभा संयोजक पवन मिश्रा तथा भाजपा युवा मोर्चा के विवेक गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, शोहरतगढ मण्डल अध्यक्ष शिवशक्ति शर्मा, नीलेश चौधरी, अरविंद चौधरी, परशुराम जयसवाल, विजय गुप्ता, दीप चन्द सहानी, श्याम गुप्ता, नवीन पाण्डेय, कुश मोदनवाल, सुजीत पाण्डेय, कृष्णा सोनी, मनोज तिवारी आदि सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी जयेन्द्र कुमार की उपस्थिति में प्रधान संघ के साथ लोहिया कलाभवन में बैठक सम्पन्न हुई।

ब्यूरो डेस्क

बैठक में प्रधान संघ द्वारा अपनी बात रखी गयी। जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 ने जनपद के ग्रामो से आये हुए सभी सम्मानित प्रधान का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 ने कहा कि मुझे ज्वाइन करते हुए जिले में बाढ़ आ गयी। मैने तत्काल टीम बनाकर कार्य किया जिसमें सर्वप्रथम ग्राम प्रधानो को रखा गया। मै स्वयं प्रधानो से लगातार फोन पर बात करता रहा। इसके साथ बाढ़ कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया, आप लोगो ने अच्छा कार्य किया इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।

यह जनपद आकाक्षी जनपद है मुझे यहां शत-प्रतिशत कार्य करना है जिससे जनपद विकसित जनपद की ओर बढ़े। मेरे कार्यकाल में जो भी कार्य हो रहे है वह सभी कार्य समय से एवं गुणवत्तापूर्वक

होना चाहिए। इसके साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ का लाभ गांवो के अन्तिम व्यक्ति तक पहुचे इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। सामुदायिक शौचालय समय से खुलना चाहिए। इसके साथ ही ग्रामो में साफ-सफाई व्यवस्था ठीक होना चाहिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि गर्भवती महिलाओ को चिन्हित करे तथा उनका रजिस्ट्रेशन कराये तथा उनका नियमित टीकाकरण भी कराये।मुख्य विकास अधिकारी श्री जयेन्द्र कुमार ने कहा कि विभिन्न विकास खण्डो के ग्रामो से आये हुए प्रधानो को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि गाम पंचायतो में विकास से संबधित जो भी कार्य कराये जाये वह सभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार गुणवत्ता मानक के अनुरूप कराया जाये जिससे किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाये। जिला प्रशासन द्वारा आप सभी लोगो को हर सम्भव सहयोग प्रदान किया जायेगा।इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी गोपाल प्रसाद कुशवाहा, पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, डी0सी0मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार, जिलाध्यक्ष प्रधान संघ पवन मिश्रा एवं समस्त विकास खण्डो के प्रधान संघ के पदाधिकारीगण व ग्राम प्रधान आदि उपस्थित थे।

महिला समूह में हुआ 64 लाख का गोलमाल

राम् गौड़ ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

विकास खंड बर्डपुर के ग्राम पंचायत बर्डपुर 11 के विभिन्न टोले के 16 महिलाओं के नाम से 64 लख रुपए का लोन कराने वाली महिला और एक सीएससी संचालक तो जेल में हैं लेकिन अब इन महिलाओं के नाम से हुए लोन कि भरपाई कैसे हो इन गरीब महिलाओं को तो खाने को लाले पड़े हैं लोन का किस्त कैसे कहां से जमा करें इस प्रकरण का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है लोन देने वाले बैंक के कर्मी इन महिलाओं के घर आते हैं गाली गुप्ता देते हैं और पैसा न मिलने पर और पंखा मोबाइल तक उठा ले जाते हैं, महिलाओं का कहना है कि यदि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर होंगे।

जिलाधिकारी डॉ राजा गणपति आर की लोकप्रियता

ब्यूरो डेस्क

डुमरियागंज! जनपद सिद्धार्थनगर के वर्तमान जिलाधिकारी डॉ राजा गणपति आर ने अपने काम के बल पर लोकप्रियता इतनी हासिल कर ली है कि जनपद के अधिकांश लोगों के जुबान पर डीएम साहब के कार्यशैली की लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं आप फोटो में शर्ट पर पसीने के निशान से अनुमान लगा सकते हैं की AC ऑफिस छोड़कर जनता की सुख सुविधा के लिए गली-गली में पसीना बहा रहे हैं आईएएस बनने के बाद जहा लोग ऑफिस में ही मजे करते रहे हैं यही कल्चर रहा है, अभी तक लेकिन जब से जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी के रूप में मौजूदा डीएम साहब आए हैं तब से यहां स्थिति बदल चुकी है कल डुमरियागंज में इटवा बढ़नी रोड पर खीरा मंडी के समीप दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुआ था जिसमें गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई थी महिला की 4 वर्षीय बेटी की मृत्यु हो गई थी गर्भवती महिला के पेट से बच्चा बाहर निकल गया था उसकी भी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी घटना से आहत जिलाधिकारी महोदय ने घटना को स्वयं संज्ञान लिया और आज जिला मुख्यालय से डुमरियागंज आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया घटनास्थल पर दुर्घटना का कारण जानने के बाद बहुत नाराज दिखे प्रशासन द्वारा जप्त गिट्टी मोरंग को उन्होंने मंदिर चौराहे पर बने गड्ढे में बराबर करवा दिया, घटना के बाद घटना से आहत ना तो क्षेत्र की विधायक ना ही सांसद महोदय दिखे हमेशा फेसबुक पर छोटी-छोटी बात को पोस्ट करते रहते हैं यहां के जनप्रतिनिधि लेकिन उक्त दुर्घटना से यहां के जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो काम नेताओं को करना चाहिए वह कार्य अब जिला अधिकारी महोदय कर रहे हैं जो यहां के जनता के लिए सुखद है और यहां के नेताओं के लिए बहुत ही दुखद है विधायक सांसद बनने के बाद लोग अपने AC गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कल का दुर्घटना इतना पीड़ा दायक है कि अगर आप सोच लेंगे की एक गर्भवती महिला के पेट से बच्चा बाहर आकर उसकी भी मृत्यु हो जा रही है उसकी मां की मृत्यु हो जा रही है तो आप कल्पना करिए की घटना कितना दर्दनाक रहा होगा लेकिन यहां के नेताओं को जरा सा भी शर्म नहीं है जो उक्त घटना से दुखी हुए हैं सड़क के किनारे अतिक्रमण के कारण आए दिन अधिकांश दुर्घटनाएं इसीलिए हो रहा है की सड़क की पटरियों पर गिट्टी मोरंग की दुकान वाले आसपास के दुकान वालों का अवैध कब्जा रहता है और प्रशासन जब कभी अतिक्रमण हटाने की कोशिश करता हैं तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व्यापार मंडल और नेता नगरी पक्ष विपक्ष सभी लोग मातम करने लगते हैं विरोध करने लगते हैं अतिक्रमण की वजह से जिसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया उससे पूछिए उसके परिवार से पूछे कि दर्द कितना होगा मौजूदा जिला अधिकारी के कार्यशैली से जनपद वासियों को बहुत ही उम्मीद है हीरो की तरह जिलाधिकारी महोदय इसी तरह कार्य करते रहें ईश्वर उनको और सशक्त बनाए और जनपद के नेताओं को मुंह छुपाने के लिए मजबूर हो जाना पड़े जिलाधिकारी महोदय ने डुमरियागंज प्रशासन को सख्त आदेश दिया है अतिक्रमण हटाने के लिए नगर प्रशासन आक्रमण हटाने के लिए लाउडस्पीकर से संदेश प्रसारित करवा रही है यह सुनकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं में खलबली मची है कि अतिक्रमण न हटे लेकिन अतिक्रमण हटेगा क्योंकि जिले में एक ईमानदार जिला अधिकारी हैं जो सही को सही और गलत को गलत करने की क्षमता रखते हैं ऐसे अधिकारी को दिल से सलूट

भारत में ओबीसी

सामाजिक असमानता को दूर करने की दिशा में

अंकित यादव
छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय

OBC क्या है? यही से शुरू करते है। अगर बात करे OBC के बारे मे तो पहले इसका मतलब समझना जरूरी है, OBC उन लोगों का समूह है जिन्हे ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और शिक्षा मे पिछड़ा माना गया। यह एक सरकारी वर्गीकरण है। यह सामाजिक समूह को संदर्भित करता है जो समान्य रूप से उच्च जातियों से सामाजिक बराबरी नही कर पाए। यह सामाज बीच मे फंस गया, इन्हे उच्च जातियों उतने अवसर नही मिले और सामाज मे पीछे रह गए। इनकी लडाई मुख्य धारा मे आने की अभी भी जारी है। राजनीति का शिकार बना OBC।OBC अपने ऐतिहासिक कारणों से तो पीछे रहा ही पर आज़ाद भारत मे राजनीति का शिकार होने के कारण पीछे रह गया और आज तक होता ही रहा है।

1931 के जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश मे OBC की जनसंख्या 52 प्रतिशत है, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अपने मुद्दों पर लड़ नही पाता है यह समाज।इसका एक मुख्य कारण है लगातार राजनीति का शिकार हो जाना। क्योंकि इस समाज को एक बड़ा नेता का नेतृत्व न मिल पाना। इस समाज ने बड़े बड़े नेता इस देश को दिया पर अपने समाज के हितों की बात करने के लिए एक नेता नही दे पाया। इस समाज से जो भी नेता आते है वो किसी एक जाति विशेष का होकर रह जाते है, या तो वो खुद उस जात की राजनीति करके आगे आता है या उस जात के लोग खुद उसे अपने जात का नेता स्वघोसित कर देते है। पर सोचने की बात ये है की ऐसा होता क्यों है।

इसका एक मुख्य कारण ये है की अपने आस पास की जातियों से सामाजिक तथा वैचारिक टकराव, वर्चस्व की लडाई आदि। अपने जाति का वर्चस्व जमाने मे लग जाना, आपस मे ही खुद को सर्वश्रेष्ठ बोलना और खुद OBC की सबसे बड़ी जाति बोलना। इसका सीधा उदाहरण देख सकते है जैसे यादव समाज ने अपना नेता अखिलेश को चुना, राजभर समाज ने ओम प्रकाश राजभर को, पटेल समाज ने अनुप्रिया पटेल को, मौर्य समाज ने केशव प्रसाद मौर्य को चुना आदि।

पर हमे ऐसा SC/ST समाज मे देखने को नही मिलता है उस समाज ने एकता दिखाया और अपने आंदोलन को मजबूत करते हुए हमेशा से एक नेता को चुना जिससे आंदोलन को सही दिशा मिल सके जैसे की मायावती और इसका फलस्वरूप यह हुआ की कम से कम ST/ST समाज ने वैचारिक लडाई तो जीत ली है। वही OBC समाज के पास ऐसा नेतृत्व न होने के कारण उनका आंदोलन हमेशा कमजोर रहा।OBC समुदाय बहुत सारी जातियों से मिलकर बना है और उन जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ होने के कारण टकराव हो जाता है, और वही पर जातिगत पहचान की भावना उत्पन्न होने के कारण भी एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा और विरोध की भावना पनप जाती है, जिससे आंतरिक कलह होती है। वही आरक्षण भी एक कारण है इसका लाभ प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपजाति के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कलह हो जाती है, जिससे भी सामुदायिक एकता मे कमी आती है। सामाजिक विकास की ओर अग्रसरOBC समाज को यह समझना होगा की अगर उन्हे सामाजिक न्याय चाहिए तो आपसी टकराव से उपर उठकर एक साथ आकर अपने हक के लिए लड़ना होगा।

आपसी टकराव सीधा सीधा सामाजिक उत्थान मे बाधा डालती है। इसे सही करने के लिए जो OBC नेता है उन्हे समुदाय के भीतर आंतरिक कलह, असमानताएं को कम करने पर ध्यान देना होगा, जिससे समुदाय के भीतर एकता बढ़ेगी और समुदाय मजबूत होगा। जब समाज मजबूत होगा तो अपने मुद्दे को एक साथ लेकर चल पाएगा और इससे समाज लगातार प्रगति करेगा।

बहुजन पहचान पर प्रश्न चिन्ह

अजीत कुमार
छात्र D.U.

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण लाभों से अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने की आवश्यकता व्यक्त की हैं। आसान भाषा में कहें तो मूल रूप से वे दलितो की पूरी पीढ़ीगत क्षति, अपमान, आघात, भुखमरी, मृत्यु, बलात्कार, अत्याचार आदि को मौद्रिक रूप में बदलना चाहते हैं, जहाँ हमारी पहचान हमारे पास मौजूद धन की मात्रा से निर्धारित होगी।

यह वास्तव में दलित समुदायों को दी गई संवैधानिक पहचान को कमजोर करने और दलितों की स्थापित सामूहिक चेतना को नष्ट करने का एक प्रयास है। हालाकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान में एससी-एसटी की सूची में एडिशन, डिलिशन और मोडिफिकेशन का अधिकार नही है।उप-वर्गीकरण के समर्थकों का तर्क है कि आरक्षित समुदायों के भीतर कुछ परिवार अब संपन्न हो गए हैं और आरक्षण के लाभों को अपने पास रखना चाहते हैं। उनका सुझाव है कि उप-वर्गीकरण की अनुमति न देने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहाँ उनमें से संपन्न लोग सभी लाभों को हड़प लेंगे और अन्य उप-जातियाँ पीछे रह जाएँगी।अनुसूचित जाति और जनजाति में कुछ उप-जातियों का प्रतिनिधित्व वास्तव में कम हैं जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की नीतियां बनाने का निर्देश देना चहिए ताकि वे भी आरक्षण नीति का पर्याप्त उपयोग कर सकें।

परंतु सर्वोच्च न्यायालय बेतुके निर्देश दे रहा है जैसे मानो कि एक निश्चित मात्रा में धन प्राप्त करने के बाद जाति समाप्त हो जाएगी।वे भूल जाते हैं कि आरक्षण (सकारात्मक कार्रवाई) की अवधारणा गरीबी उन्मूलन योजना के रूप में नहीं बल्कि उन विशेष

समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी जिनके साथ सदियों से भेदभाव किया गया है। इसका उद्देश्य हर क्षेत्र में सरकार के निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। अनुसूचित जातियों को एक समरूप समूह के रूप में मानने के पीछे तर्क यह था कि इस वर्ग की सभी जातियां हिंदू धर्म के भीतर अस्पृश्यता से समान रूप से पीड़ित थीं। अब सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश उन उप-जातियों के बीच एक गलत धारणा पैदा करेगा जो अपेक्षाकृत पिछड़ी हैं कि उनका पिछड़ापन या कम हिस्सेदारी उन्हीं के वर्ग के अन्य उप-जातियों द्वारा भेदभाव के कारण है।

यह समाज के दबे-कुचले तबके की एकजुट चेतना को खतरे में डाल सकता है।इसके अलावा उप-वर्गीकरण के कुछ अन्य प्रमुख नुकसान हैं मसलन,1.राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एकजुट चुनावी ताकत का ध्रुवीकरण करने के लिए कर सकते हैं। - वे राजनिति दल जिनका वोट बैंक मुख्य

रूप से तथाकथित उच्च जातियां हैं वो इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने के क्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में "फूट डालो,राज करो" के सिद्धान्त पर आगे बढ़ेंगे और अपने वोट बैंक का विस्तार करेंगे। वो कुछ उप-जातियों के बीच एक गलत धारणा पैदा करने की कोशिश करेंगे कि उनके कम प्रतिनिधित्व का कारण उन्ही के समाज के कुछ लोग है जो आरक्षण का

सारा लाभ ले रहे है और ये भरोसा दिलाएंगे की उन उप-जातियों को अलग से आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये दलितो के राजनितिक समझौते की शक्ति को कम करेगा।

2. इसका इस्तेमाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को उनके कोटे की सीटों तक सीमित रखने या प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिरोध उपकरण के रूप में किया जा सकता है।- आरक्षण का व्यापक रूप से कार्यान्वयन तभी माना जाएगा जब आरक्षित वर्ग के लोग अनारक्षित सीटों पर तथाकथित मेरिट से पहुंचने लगे। परन्तु ऐसा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए उप वर्गीकरण का प्रयोग किया जा सकता हैं। अनारक्षित सीटों पर वही आरक्षित वर्ग के लोग पहुंच सकते है जो उनमें आधुनिक वातावरण में रहकर आर्थिक और शैक्षिक रूप से बेहतर हो। पर अगर उप वर्गीकरण करके ऐसे लोगो को आरक्षित वर्ग से क्रीमी लेयर बताते हुए बाहर कर दिया जाए तो फिर बाकी बचे उप-जातियों के लिए अनारक्षित सीटों पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा जो आर्थिक और शैक्षिक रूप पीछे है

3.इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की निरंतर रिक्तता बनी रहेगी।- चुकी केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े उप जातियों के लिए कोई भी विशेष नीति नहीं चलाई गई हैं ताकि वो आरक्षण का लाभ ले सकें। जिसके फलस्वरूप आराक्षित सीटो पर उपयुक्त उम्मीदवार ना मिलने की वजह से खाली रह जायेगी और आरक्षित सीटो की रिक्तता बनी रहेगी। इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च पदों तक पहुंचने के अवसर और कम हो सकते हैं।4 इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश साफ तौर पर कुछ उप-जातियों के कम प्रतिनिधित्व के पीछे के वास्तविक कारण को छिपाने या दरकिनार करने का प्रयास प्रतीत होता है।

क्या दुनिया को है सन्देश जलता हुआ बांग्लादेश?

ब्यूरो डेस्क

किसी देश में तख्तापलट की संभावना आमतौर पर तब बनती है जब देश के तमाम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं या फिर सरकारें तानाशाह बन जाती हैं यानी सरकारों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अपने मन का ही करती हैं, चाहे उससे जनता का भला हो या नुकसान हो। इसके अलावा तख्तापलट की एक संभावना तब बनती है जब सेना को सरकार से खतरा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में सेना ही सरकार के खिलाफ आ जाती है और तख्तापलट करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है। आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा।अपने देश में भी इन दिनों जाति को लेकर घमासान मचा हुआ है। भारत में भी जाति और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर संसद में 'राजनीति' चरम पर है और सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण सम्बन्धी हालिया फैसले ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। बांग्लादेश संसद में वाद विवाद संवाद व्यवस्थित नही रहा, बांग्लादेश संसद ने जनता का यक़ीन खो दिया, बांग्लादेश में जो हालात बेकाबू हुए इससे साबित होता देश में जनता से बड़ा कोई नही, कुछ गलत निर्णय देश को सालों साल पीछे धकेल देते। गलत निर्णय कितने भारी पड़ गए बांग्लादेश को।

बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अपना देश छोड़कर जा चुकी हैं, जिसके बाद यहां की सत्ता अब सेना के हाथों में चली गई है। माना जा रहा है कि अब आर्मी चीफ जनरल वकार-उज-जमान देश की कमान भी संभालेंगे। किसी देश में तख्तापलट की संभावना आमतौर पर तब बनती है जब देश के तमाम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं या फिर सरकारें तानाशाह बन जाती हैं यानी सरकारों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अपने मन का ही करती हैं, चाहे उससे जनता का भला हो या नुकसान हो। इसके अलावा तख्तापलट की एक संभावना तब बनती है जब सेना को सरकार से खतरा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में सेना ही सरकार के खिलाफ आ जाती है और तख्तापलट करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है। पाकिस्तान में भी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा ही किया था। उन्होंने नवाज शरीफ को सत्ता

से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो गए थे। आंकड़ों के अनुसार 1950 से अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 400 से भी अधिक बार तख्तापलट हो चुका है। इस मामले में दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया टॉप पर है। यहां अब तक 20 से भी अधिक बार तख्तापलट हो चुका है। इसके अलावा इराक में 10 से भी अधिक बार और पाकिस्तान में 4 बार तख्तापलट हो चुका है। वहीं, अफ्रीकी देशों में भी 10 से अधिक बार तख्तापलट हुआ है।

बांग्लादेश साल 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। साल 1972 में इसे बतौर देश मान्यता मिली थी। 1972 में तत्कालीन सरकार ने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हालांकि, साल 2018 में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। हालांकि, इस साल जून में हाईकोर्ट के फैसले ने इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए इसे दोबारा लागू कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने में विरोध प्रदर्श शुरू हो गए। शेख हसीना सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसने हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल पांच फीसदी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होगी। दो फीसदी नौकरियां अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को होनी थी लेकिन, इससे पहले विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरियों में एक तिहाई आरक्षण के विरोध में फैसला दिया और आरक्षण की सीमा को घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया। मगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए और वह इस आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करते रहे। सरकार के सख्त रवैये से उनकी नाराजगी और बढ़ती गई। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बड़ी चर्चा होती है और वह दुनिया की सबसे तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। शेख हसीना के 15 वर्ष के शासनकाल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली है।मगर बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का लाभ सबको नहीं मिल रहा जिससे वहां असमानता बढ़ रही है। एक अनुमान है कि वहां लगभग1। 80 करोड़ युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों में बेरोजगारी की दर और भी ज्यादा है।बांग्लादेश टेक्स्टाइल क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और वहां बने रेडिमेड कपड़े सारी दुनिया में निर्यात होते हैं। इस उद्योग में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मगर इन नौकरियों में कॉलेजों के पढ़े-लिखे छात्रों के लिए संभावनाएं बहुत कम हैं। इन्हीं वजहों से बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था और यही वजह है कि छात्रों का आरक्षण विरोधी आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और शेख हसीना की सत्ता गिर गई।

महिलाएं और उनकी अनचाही दीवारें

बुशरा खान
छात्रा जामिया मिल्लिया इस्लामिया

अगर हम महिलाओ की दशा देखें, तो हम इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओ को ,समाज और परिवार दोनो जगह, दोयम दर्जे पर रखा गया है !अतीत की तुलना आज से करे तो महिलाओ के पास सीमित आज़ादी तो है। जिसकी सीमा पहले से ही तय है। चिंतित समाज अपनी सहूलत के हिसाब से परिवर्तित कर रहा है। समाज के हिसाब से चले तो वह सशक्त महिला है , समाज के खिलाफ अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ले तो समाज के इसलिए हस्तक्षेप बन जाता है। फिर परिवार अपनी ही घर की औरतो को सीमित कर देता है थोड़ा पढ़ लो, सिलाई सीख लो, आगे काम आएगा ।डिग्री तो होती है इनके पास पर वह चार दीवारों तक ही सीमित रह जाती है। दोयम दर्जे का होना या बन जाना बहुत घातक रहा, इन महिलाओ के लिए।

जो मानव श्रम मे सबसे आगे पाई है , अव्वल होने के साथ भी दर्जा दोयम रहा। दोयम , औरतों को उनके परिवार ने बनाया। और समाज ने भी अच्छी भूमिका निभाई। अगर हम सारी स्थितियों को समझे और टटोले जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला होना और महिला हो के जीना एक कठिन संघर्ष रहा है।महिलाओ को उनके वजूद से बांध दिया जाता है ,चाहे वो बंधान चाहे या ना। सोच कर देखिए महिला और उनकी अनचाही दीवारों को।

मुख्य समस्याएं

अधिकारों से वंचित। क्या है इनके अधिकार बराबरी का अधिकार ? अधिकारों के नाम पर शिक्षित होती भी है तो सिर्फ इतनी ही जिनकी एक परिवार को चला सके ।अधिकारों से वंचित होगी ।तभी तो पूर्ण महिला कहलाए जाएगी। अपने अधिकारों को समझ लेगी तो बराबरी का अधिकार मांगेगी, और अपने सपनो से समझौता नहीं करेगीआखिर क्यों मजबूर हो कर अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाती है। प्रेम विवाह, जबरन शादियां, दहेज, बेटा पैदा करने मे असमर्थ तक़रीबन इन्ही मामलों से गुजरती है। उनको घर छोड़ना चाहिए तो अपनी किताबों के साथ , किताबों ने ही सबसे ज्यादा महिलाओं को आज़ाद किया है। ये संघर्ष उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन महिलाओ ने पढ़ने का हक मागा।

शिक्षा मे भेदभाव क्यो?

अगर हम देखें भारत के सरकारी स्कूलों मे लड़कियो का आंकड़ा लडको के मुकाबले ज्यादा है ज्यादातर देखा जाता है, परिवार के पास, अगर सीमित धन है, तो उस परिवार का ये मूल कर्तव्य बन जाता है अपने बेटे हो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल मे दाखिला करवा दे वही अपनी बेटियो को सरकारी स्कूल मे भेज देते है। भेदभाव तो है आखिर ये भेदभाव कहां और कब तक, जन्म से भेदभाव, शिक्षा से भेदभाव, सपनो से भेदभाव, इन भेदभाव के चलते लाखों करोड़ों महिलाओ के सपनो का

अंत हो जाता है।

राजनीति में महिलाओ की भागीदारी।

सर्वेक्षण में पाया गया, महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति प्रभावी रही। उच्च सामाजिक वर्ग (जाति) व आर्थिक वर्गो की महिलाओ में राजनीतिक भागीदारी अधिक पाई गई। जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक तबके की महिलाओ की भागीदारी कम पाई गई है इनके अनेक कारण है निम्न शिक्षा , आर्थिक स्थिति, एक्सपोजर में कमी, अवर होना इत्यादि। अगर ग्रामीण इलाकों में नज़र दौड़ाई जाए, तो महिलाऐं राजनीति मे सबसे नीचे पाई जाएंगी। उनकी राजनीति सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित रह जाती है , ग्रामीण महिलाऐं राजनीति से कोसो दूर पाई जाती है। जहाँ तक बात बराबरी की है और बराबर के अधिकारों की है, यह संविधानों और कानूनों मे पाए तो गए है परंतु यह समाज के किसी भी पहलुओं मे स्थित नहीं हुए है!

जेंडर गैप पे पैरिटी।

जेंडर गैप की खाई तो बहुत गहरी है, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना प्राचीन समय से ही शुरू कर दिया, सबसे पहले ये लड़ाई हमें फ्रांस के समाज में देखने को मिली। फ्रांस की महिलाएं कई दशकों तक पैसिव सिटीजन में रखी गई फ्रांस का समाज तीन एस्टेट में विभाजित तो था। पहला एस्टेट क्लर्जी, दूसरा नोबेलिट, और तीसरा 90%वाला एस्टेट पहले और दूसरे एस्टेट की महिलाओ को शिक्षित तो किया जाता था, सिर्फ उतना जिससे की उनकी बड़े घर में शादी हो सके। संघर्ष तो तीनों एस्टेट की महिलाओ के लिए था। ये संघर्ष धीरे धीरे संघर्षो मे तब्दील हो गया। वह लड़ी वोटिंग राइट्स, इक्वल वेजेस के लिए , फ्रांस की क्रांति से ले कर 1946 तक संघर्ष की कतारें जारी रही फ्रांस के साथ साथ अनेकों देशी में भी। ओलिंप दे गैंग्स वह महिला थी जो अकेले फ्रांस की अव्यवस्थित सामाजिक संरचना से लड़ी और पूरी दुनिया की महिलाओ के संघर्ष की कहानी बनी।

भारत में पे पैरिटी की बात करे तो अभी भी इक्वल पे नहीं है मनोरंजन जगत मे निरंतर ये असमानता देखी है है जहां अभिनेता को ज्यादा वेतन मिलता है अभिनेत्री के मुकाबले। पे पैरिटी अगर देखने को मिलती है वो है सरकारी नौकरियां

दो क़दम पीछे : भारत और वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी 2024 के

वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के मुताबिक भारत

146 देशों में 129वे स्थान पर है ।

अब से लैंगिक अंतर को समाप्त करके और महिलाओ के विरुद्ध भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने में 286 वर्ष लगेंगे, तथा राष्ट्रीय सांसदों में लैंगिक समानता

प्राप्त

करने मे कम से कम 40 वर्ष लगेंगे।

निष्कर्ष

भारत एक प्रगतिवादी की ओर अग्रसर तो हो रहा है है परंतु आज भी महिलाऐं अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रही है। उनका संघर्ष प्राचीन काल से चलता आ रहा है ये संघर्ष बराबरी, इक्वली पे पैरिटी, वॉयलेंस, ख़ुद को दोयम दर्जे से मुक्त, समानता और इक्वल दर्जे का चाहती है। समाज और इतिहास ने किस तरह से नाइंसाफी की है। हर वो लड़की पूछेगी जब वह अपने वंचित अधिकारों को जान लेगी। तब प्रश्न पूछे जानेंगे।

भ्रष्टाचार की साझेदारी ?

ब्यूरो डेस्क

अखिलेश यादव ने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही,पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया। जनता के ग़ुस्से से बचने और दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के ख़िलाफ एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करे। गुजरात भेजकर उसकी संपत्ति वसूलने की हिम्मत दिखाए। ऐसे आपराधिक लोग उत्तर प्रदेश के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार साबित करे कि वो इन अपराधियों के साथ है या प्रदेश की जनता के साथ। भ्रष्टाचार की साझेदारी..?

उत्तर प्रदेश में काम करने वाली हर कंपनी के इतिहास और उसकी सत्यनिष्ठा-गुणवत्ता की जाँच की जाए। जब बेईमान और कलंकित कंपनियों को काम दिया जाए तो जनता को समझ लेना चाहिए कि इसमें काम देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के उस मंत्रालय और उसके विभाग के लोगों की भी हिस्सेदारी है मतलब 'ये भ्रष्टाचार की साझेदारी' है। इस परीक्षा के आयोजन से संबंधित कंपनी ही नहीं बल्कि हर एक संलिप्त मंत्री या अधिकारी की भी जाँच हो और जब तक जाँच पूरी न हो जाए, तब तक उसे उसके काम से मुक्त रखा जाए और संलिप्तता

सिद्ध होने पर बर्खास्त करके कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

अखिलेश यादव ने कहा कि हम माँग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम कर रही या काम करने की इच्छुक हर बाहरी कंपनी की गहन जाँच हो और सब कुछ सही पाये जाने पर ही काम दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर जब काम गलत होता है तो उससे उत्तर प्रदेश की छवि को ठेस पहुँचती है और प्रदेश के पैसों की बर्बादी भी होती है। इन सबका ख़ामियाज़ा आख़िर में आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। साथ ही ये भी माँग है कि उत्तर प्रदेश की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए। बाहरी कंपनियों को तभी काम दिया जाए जब यूपी के सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों या स्थानीय कंपनियों के पास कार्य कराने के अनुभव का अभाव हो।

यूपी की जनता ये भी याद रखे कि ये वो ही भाजपा सरकार है, जो कल तक ठेके पर पुलिस रखने का फ़रमान निकाल रही थी। घोर निंदनीय है। अखिलेश यादव ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। भ्रष्टाचार की साझेदारी..?

उत्तर प्रदेश के आक्रोशित युवा पूछ रहे हैं कि यूपी के बुलडोज़र के पास बाहर के राज्यों में जाने का लाइसेंस और साहस है क्या? और ये भी कि जिस मंत्रालय के तह त पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसके मंत्री और अधिकारियों की तरफ़ बुलडोज़र मुड़ता भी है या नहीं।

यूपी की जनता ये भी याद रखे कि ये वो ही भाजपा सरकार है, जो कल तक ठेके पर पुलिस रखने का फ़रमान निकाल रही थी। घोर निंदनीय है। अखिलेश यादव ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। ■

केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है, यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है।

ब्यूरो डेस्क

संयुक्त सचिव, उप-सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली है लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की नियुक्ति करती तो उसे और को आरक्षण देना पड़ता यानि में से अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्धऔर शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियाँ और उनके नेता छाती पीट-पीटकर दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक-अधिकार नहीं खा सकता लेकिन उनकी आँखों के सामने, उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है तथा कथित स्वयंभू समेत उनके साथ यूपी-बिहार-झारखंड के और नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट ठहाके लगा रहे है। देश की फ़ीसदी आबादी का हक़ खाने वालों को जनता माफ़ नहीं करेगी। जागो "दलित-पिछड़ा-आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग" जागो! हिंदू के नाम पर ये आपका हक़ खा रहे है तथा आपके अधिकारों की बंदरबांट कर रहे है।

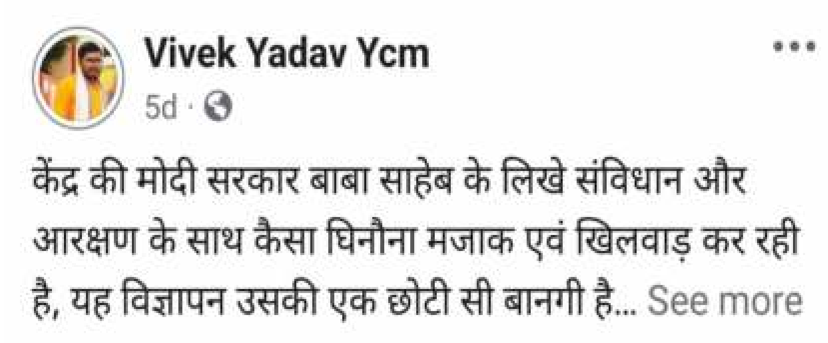

2027 का चुनावी रण अखिलेश कितने तैयार

उत्तर प्रदेश को अपना 33वां मुख्यमंत्री मिला था नाम अखिलेश यादव

आनंद यादव
पत्रकार

मार्च 15, 2012 को उत्तर प्रदेश को अपना 33वां मुख्यमंत्री मिला नाम था अखिलेश यादव पिता तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके थे जिम्मेदारियां बड़ी थी लेकिन उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने 5 साल सरकार चलाई तो आज भी उसको टक्कर देने के लिए भाजपा 10 साल होने के बाद भिवदूर-दूर तक कहीं नजर नहीं आती है।

5 साल की सरकार चलाने के बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरी हार नसीब होती है कारण बहुत से थे लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि समाजवादी पार्टी का जो नारा था "काम बोलता है" वह जनता के बीच में शायद नहीं पहुंच पाया फिर 2022 चुनाव आया जब लगा कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित वोट परसेंटेज मिला। आंकड़े बताते हैं कि 100 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी के विधायक बहुत कम वोटों से हारे। आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 5 लाख वोट और मिल जाते हैं तो समाजवादी पार्टी इस समय सत्ता में काबिज होती। फिर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को बसपा के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं हुआ जबकि बहुजन समाज पार्टी जो 2014 में 0 पर सवार थी वह 10 सीटों के साथ यूपी में दूसरी बड़ी पार्टी बनने के बाद में बहन जी ने सपा पर ही आरोप लगाकर गठबंधन को तोड़ लिया। साल आता है 2024 जब तमाम राजनीतिक पंडितों का कहना था कि अखिलेश यादव के लिए 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही मायनों में उनके आगे की राजनीति दिशा और दशा तय करेगा.

अखिलेश यादव जो हमेशा से राजनीति में नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं फिर उन्होंने एक फार्मूला दिया PDA फार्मूला. PDA फार्मूला के तहत उन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश को यह संदेश दिया की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी मतलब महिलाएं और अगड़े समाज के वह लोग जो सामाजिक शोषण के शिकार हैं उन सब के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी इस बार

संविधान, आरक्षण, नौकरियों में घोटाले की लड़ाई चलेगी. अग्नि वीर योजना, पेपर लीक मामले का विरोध करेगी और 24 में INDIA ALLIANCE के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी।

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव कहीं न कहीं फिर से वही PDA फार्मूला अपनाएंगे. इसके तहत उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली थी.

अयोध्या मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतार करके अखिलेश कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी है उत्तर प्रदेश की सत्ता से 10 साल दूर रहने के बाद 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कमर कस के उतरना चाहेगी जिसमें PDA का फार्मूला उनके प्रमुख राजनीतिक हथियार होगा इसके बदौलत वह चाहेंगे कि 2027 में सत्ता में वापसी की जाए.

देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो उनकी बातों में इस देश के बेरोजगार युवाओं का दर्द नजर आता है. वह सरकार से सवाल पूछते हैं की महंगाई कम क्यों नहीं हुई सरकार से पूछते हैं की जो भाजपा अच्छे दिन का वादा की थी वह वादे कहां गए?

अग्निवीर योजना के खिलाफ अखिलेश यादव हमेशा मुखर होकर बोले हैं

अखिलेश यादव की दूरदर्शी सोच और राजनीतिक समझ की बदौलत समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. उत्तर प्रदेश का हताश और निराश हुआ अखिलेश यादव में भविष्य देखता है उसको पता है कि अखिलेश जब सत्ता में थे तो उन्होंने नौकरियां दी थी.बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला था.आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए लैपटॉप मिला था.पुलिस के तुरंत सहायता के लिए डायल 100 मिला था.एंबुलेंस की सहायता के लिए 102 मिला था.आगरा लखनऊ जैसा ऐतिहासिक एक्सप्रेस में मिला था और भी न जाने कितने ऐतिहासिक काम हुए थे.

अब देखना यह होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होती है और अगर सफल होती है तो PDA का फार्मूला कितना काम आता है क्योंकि उसके पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनाव की सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी है की एक बार फिर से PDA का फार्मूला सत्ता में वापसी का रास्ता दिखाएगा.

साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसा

ब्यूरो डेस्क

साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे साजिश करार दिया है. अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "साबरमती एक्सप्रेस (वाराणसी से अमदावाद) का इंजन आज सुबह 02:35 बजे कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया. तेज चोट के निशान देखे गए हैं. साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं. आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है. इस हादसे में यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है. यात्रियों के अमदाबाद से आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है.जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 19168 साबरमती एक्सप्रेस (बनारस-अहमदाबाद) अहमदाबाद की तरफ जा रही थी. झांसी मंलल के अंतर्गत कानपुर के भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे अचानक ट्रेन डीरेल हो गई और इसके 22 कोच पटरी से उतर गए. हालांकि हादसे में किसी भी प्रकार के जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है. न ही किसी के घायल होने की सूचना है.ड्राइवर के अनुसार, प्रथम दृष्टया बोल्डर इंजन से टकराया जिसके कारण इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त यानी मुड़ गया. इसके बाद कोच पटरी से उतर गए. वहीं, रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के सभी इंतजाम किए गए हैं. यात्रियों को बस से कानपुर सिटी भेजा जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं.वहीं, दूसरी तरफ ADM सिटी कानपुर राकेश वर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि 22 बोगियां पटरी से उतरीं हैं, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है. सभी यात्रियों को बसों से कानपुर स्टेशन भेजा जा रहा है, मेमो ट्रेन भी आ रही है. अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

भारत में समान नागरिक संहिता

ब्यूरो डेस्क

सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर इसका आग्रह किया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। । संविधान में इसका प्रावधान है। संसद और भारत सरकार यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा अथवा शरिया कानून भी संवैधानिक माना जाता रहेगा? मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर प्रहार करने की नीयत और मानसिकता किसी की नहीं है। पर्सनल लॉ तो सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि समुदायों के भी हैं। आदिवासी कबीलों से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मुस्लिम देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी हैं। जो मुद्दे सामुदायिक और राष्ट्रीय किस्म के हैं, धर्म, मजहब, जाति से ऊपर हैं, कमोबेश उनके संदर्भ में अब 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (बीएनएसएस) की धाराएं लागू होनी चाहिए। वे हिंदू-मुस्लिम समेत सभी समुदायों पर, समान रूप से, प्रभावी होनी चाहिए। यही समान नागरिक संहिता का निष्कर्ष है।

मुद्दे की बात यह है कि शरिया और कुरान की आड़ में छिपने वाला मुसलमान सबसे पहले 'भारतीय' है और यही उसकी पहचान है। यदि देश भर में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, तो संभव है कि मुस्लिम इतना भडक़ जाएं कि हिंसा का माहौल बन जाए! घरेलू हिंसा से उपजे हालात सांप्रदायिक दंगों में तबदील हो जाएं! तेलंगाना में सरेआम संवैधानिक प्रावधानों और बाल विवाह कानून समेत कई कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किशोर बच्चियों का दैहिक शोषण किया जा रहा है। संसद 2019 में तीन तलाक के खिलाफ विधेयक पारित कर कानून बना चुकी है। फिर भी मुस्लिम मर्द 15-16 वीं सदी के समाज में जीना चाहता है!

भारत एक संवैधानिक गणतंत्र है अथवा

केला (बनाना) गणतंत्र...! क्या ऐसा संवैधानिक उल्लंघन जारी रहेगा? मुद्दा सर्वोच्च अदालत के हालिया फैसले से फिर उभरा है। दो न्यायाधीशों की पीठ का आदेश है कि मुस्लिम मर्द (पति) तलाकशुदा पत्नी को न्यायिक गुजारा-भत्ता देगा। अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद मुस्लिम धर्मगुरु, मौलाना, नेता, विशेषज्ञ आदि चीखने लगे, बौखला उठे और तिलमिलाने लगे कि यह फैसला शरिया के खिलाफ है।

शरिया और कुरान में मुस्लिम तलाकशुदा औरत को गुजारा-भत्ता का कोई जिक्र नहीं है। मामले को 1986 के **'शाहबानो प्रकरण'** की ओर मोड़ा जाने लगा है। उस समय संसद ने सर्वोच्च अदालत का फैसला पलट दिया था और तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम मौलानाओं के दबाव में, वोट की खातिर, घुटने टेकते हुए ऐसा कानून बनाया, जो आत्मा से मुस्लिम औरत

के खिलाफ था। शाहबानो भी 40 साल के वैवाहिक जीवन और 5 बच्चों को जन्म देने के बाद सडक़ पर आई थी, लिहाजा उसे अदालत की शरण में जाना पड़ा।

सवाल यह है कि क्या मुसलमानों में विवाह की परिणति यही होती है कि जब मन आया, तब औरत को छोड़ दिया और गुजारा-भत्ता भी नहीं दिया। कहा जाता है कि अब 'इद्दत' के तीन महीनों के दौरान ही तलाकशुदा औरत को गुजारा-भत्ता दिया जाता है और बच्चों की परवरिश के लिए मात्र दो साल की उम्र तक आर्थिक मदद दी जाती है। उसके बाद की जिंदगी की जिम्मेदारी मुस्लिम औरत पर ही है। सवाल है कि क्या कुरान और शरिया में ऐसी मानवीय क्रूरता के जिक्र हैं? क्या तीन माह के बाद औरत का और 2 साल की उम्र के बाद बच्चे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? आखिर वे औलादें कहां से और कैसे आई हैं? ये तमाम विवादास्पद सवाल हो सकते हैं। सोच और उसकी व्याख्याएं भी भिन्न हो सकती हैं। शरिया और कुरान को सांगोपांग शायद ही किसी ने पढ़ा हो, लेकिन क्या सर्वोच्च अदालत के फैसले और बी एन एस एस की धारा 144 की अवमानना की जा सकती है? क्या ऐसा करना अपराध नहीं होगा? संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों और आरक्षण के लिए तो मुस्लिम मौलानाओं को खूब याद आता है, लेकिन औरत के भरण-पोषण सरीखा मुद्दा हो, तो शरिया की आड़ लेने लगते हैं। दरअसल यह मामला सामाजिक समानता और लैंगिक समानता का ज्यादा है। संविधान ने दोनों ही स्थितियों के लिए समता का अधिकार दिया है। जरा वे भी कुछ बयानबाजी कर दें, जो चुनाव के दौरान संविधान की प्रति को लहराते हुए झूठे नेरेटिव का प्रचार कर रहे थे और जिन्हें मुसलमानों के लबालब वोट मिले। उसमें मुस्लिम औरतों के भी वोट होंगे!

पिछड़ा होना गुनाह है, और पिछड़ा होकर सामाजिक मुद्दों पर बेबाक होना और बड़ा गुनाह है।

आजादी दिलाने को जान हथेली पर रखकर खड़ा आज का भगत सिंह

विवेक यादव
फाइल फोटो

आज़ादी मिले हुए 78 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन गुलामी की बेड़ियां टूटने का नाम नहीं ले रही हैं।देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले में एक गांव है गोशंदेपुर।यूं तो गाज़ीपुर जिले को लोग 'शहीदों की धरती', 'वीरों की भूमि' तमाम नामों से नवाजते हैं , यहां के लोग देश के लिए मरने–मारने को हमेशा तैयार रहते हैं।गाज़ीपुर के मिट्टी के कड़–कड़ में वीरता भरी हुई है लेकिन एक हकीकत उससे इतर भी है वहां के पिछड़े–दलित कितने पिछड़े हैं, दहशत में हैं, दबे हुए हैं कि इसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। ये हमें देखने को तब मिला जब करंडा थाना क्षेत्र के गोशंदेपुर गांव में एक ढ़ाई साल की अबोध बच्ची के साथ बलात्कार एक 50–55 साल के गांव के ही मनबढ़ के द्वारा कर दिया जाता है। ऐसी जघन्य और मानवता को शर्मशार करने वाली घटना होने के बावजूद एक व्यक्ति या नेता इस मामले में एक शब्द बोलने या परिवार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हो रहा था जबकि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रधान, बीडीसी पिछड़े या दलित ही हैं लेकिन वहां कोई इसलिए सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि बलात्कारी राजपूत था, एक सवर्ण था। उस गांव में सामंतियो के दहशत का ये आलम है कि कोई मनचला, मनबढ़ राह चलते या घर में घुसकर किसी पिछड़े या दलित की बहन, बेटी या बीबी को छेड़ दे तो भी उनके घर का आदमी नज़र झुकाए वहीं बैठा रहेगा, विरोध या बचाव करना तो छोड़िए वो आँख तक नहीं दिखा सकता। आप और हमारी सोच तक वहां नहीं जा सकती, एक ढ़ाई साल की अबोध बच्ची जिसको बलात्कार, रेप, दुष्कर्म का इल्म तक नहीं था, जो समाज को समझ नहीं सकी थी, उस अबोध बच्ची को मानवता का यह विभत्सकारी रूप देखने को मिला , उस बच्ची के दिलो–दिमाग़ में पुरुषों के प्रति कैसी धारणा बनेगी ये सोचकर ही डर लग रहा है।लेकिन गाज़ीपुर को यूं ही गाज़ीपुर नहीं कहा जाता है, वीर न पैदा होना बंद हुए हैं ना ही होना बंद होंगे, ऐसे दबे गांव से, जहां सामंतियों का बोलबाला चरम पर है जहां सामंतियो के खिलाफ़ जाने की, ज़ुल्म की मुखालफत करने की क्षमता किसी में नहीं थी ऐसे परिवेश में उसी गांव का एक युवा अपनी जान हथेली पर रखकर निकलता है और उस बच्ची के साथ खड़ा होता है और केवल खड़ा ही नहीं होता है आर्थिक मदद से लेकर कानूनी मदद तक पहुंचाता है, उस जाबांजी के लिए हमारा **'तेजस बिंदु'** परिवार इस क्रांतिकारी की प्रशंसा करता है और इसकी बेबाकी के लिए क्रांतिकारी इस्तेकबाल करता है। इस आज़ के भगत सिंह का नाम है **'विवेक यादव'** जो उसी गोशंदेपुर गांव का रहने वाला है।वो कहते हैं ना कि **"दोस्ती सरफिरों से होनी चाहिए, समझदार समय पर साथ नहीं देते"** ये बात विवेक यादव पर सटीक बैठती है क्यूंकि जब सबने मुंह फेर लिया, कानों में तेल डालकर बैठ गए, जब पीड़िता के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ उस नाज़ुक दौर में फ़ौलादी सीना लेकर सामंतवाद को चुनौती देते हुए उस मासूम के साथ विवेक यादव हर लड़ाई लड़ने को खड़ा हो गया।इस दिलेरी के लिए 'आज के भगत सिंह' की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, ये नौजवान एक प्रेरणा है उन तमाम युवाओं के लिए जो डरते हैं किसी असहाय के साथ खड़े होने में, उन्हें सीख लेनी चाहिए इस युवा से। ये युवा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफ़ाक उल्ला खां, सरदार उधम सिंह, मंगल पाण्डे का वैचारिक वारिश है।

69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

रवि कुमार गुप्ता
जर्नलिस्ट

69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय ने इस सम्बंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा।

इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए तीन माह में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी कर लेने को कहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े।

यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है।

उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ ने 69000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था।एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कटऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है।

हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

पूरे देश के लोगों को बीपी मण्डल की छवि दिखती है अनिरुद्ध सिंह विद्रोही में

चौधरी मुकेश निषाद
छात्र नेता, गाजीपुर, उ.प्र.

"उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा कोई शेर नहीं जो दमदारी के साथ पिछड़ों के मुद्दों को उठाए और धरातल पर लागू करवाने की बात करे।विद्रोही साहब पर हमें विश्वास है कि ये हमारी बात करेंगे।"

सामाजिक न्याय का योद्धा लड़ेगा चुनाव

पूरे देश में मण्डल कमीशन की अलख जगाने वाले सामाजिक चिंतक,विचारक, हकवंचित समाज की सशक्त आवाज़,मण्डल योद्धा के नाम से विश्वविख्यात अनिरुद्ध सिंह 'विद्रोही' ने विधानसभा उप चुनाव में करहल विधानसभा से ठोकेंगे ताल

"सामाजिक न्याय की लड़ाई को धार पकड़ाने के लिए और हक़ वंचित समाज को उनका हक़ दिलाने के लिए ऐसे योद्धाओं को सदन में होना चाहिए। मैं दिल से चाहता हूं कि विद्रोही जी विधायक बनें।"

भाजपा के अंदर भय, भ्रम या भीतरघात

रंजना यादव
शोध छात्रा

पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही थी वही अचानक से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही उसमें तकरार बढ़ने लगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच असहमतियों की शिकायत शुरू हो चुकी है पिछले कुछ सालों से कुछ मंत्री,सांसद और विधायक जो अपने मन मुताबिक क्षेत्र के भीतर काम नहीं कर सके थे वह भी इस दरमियान मुखर होकर सामने आ रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार में बिना घुस के कोई काम नहीं होता भाजपा सरकार के अंदर रहे विधायको कोअपने ही सरकार से शिकायत शुरू हो चुकी है जिससे भाजपा और कमजोर दिखने लगी है! जो लोग कभी खुलकर बोल नहीं पाते थे आज वह खुलकर बोलने लगे हैं यह असंतोष बहुत पहले से शुरू हो चुका था लेकिन अब तो खुलकर बाहर भी आने लगा है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण था 'उत्तर प्रदेश'पहली नजर में यह साफ लगता है किभाजपा में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है अन्यथा ऐसे परिणाम नहीं आते .. खैर दिल्ली में सरकार बनने के 1 महीने बाद पार्टी ने अपनी पराजय के कारणों को समझने के लिए मंथन चालू कर चुकी है इस प्रक्रिया में यह असंतोष भी बाहर निकलकर आया है! उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान "संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है"इन हलचलों को और तेज कर दियाहै शायद यही वजह है की उत्तर प्रदेश के और भी विधायक सांसद और मंत्रियों को बल मिल गया है! वह भी खुलकर बोलने लगे हैं ! खैर उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक इस वक्त एक साथ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं राज्य में पार्टी के भीतर की तकरार काफी पहले से शुरू हो चुकी थी पर अब वह खुलकर सामने आ रही हैइतना ही नहीं बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी अपने स्वरो को मुखर करना शुरू कर दिया है कहा जा रहा है कि योगी प्रशासन में अफसरशाहीहावी है जिसके कारण भाजपा कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं

मिल पा रहा है पार्टी केविश्वासपात्र कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब से ही असंतोष की चिंगारी एक वर्ग के भीतर बैठी हुई है!

माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि आत्मविश्वास के कारण हम लोग चुनाव हार गए वहीं एनडीए की घटक अनुप्रिया पटेल काकहना है कि आरक्षण पर हमला इसहार का बहुत बड़ा कारण है औरनिषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा कि गरीबों काघरउजाड़ेंगे तो वह हमें वोट नहीं करेंगे राजनीति में उन्होंने उत्तर प्रदेश की बुलडोजर राजनीति पर भी टिप्पणी की है हाल में लखनऊ में चले बुलडोजरों को लेकर भी टिप्पणियां हो रही है कुछ समय पहले लखनऊ के अकबरनगर में बड़े स्तर पर बुलडोजर चला कर मकान तोड़े गए थे इसके पहले अपना दल यस (S) की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य में ओबीसी और अनुसूचित जाति के कोटे की सीटों पर सामान्य केटेगरी के लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं जो बातें पहले दबे छुपे कहीं जा रही थी वह अब मुखर होकर कहीं जा रही हैं !

उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है उसका बड़ा उदाहरण अभी देखने को मिला जब 69000 शिक्षक भर्ती मामले में जहां विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी,बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस योगी सरकार को निशाने पर ले रहे थे तो वहीं वर्तमान सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सरकार के साथ ना खड़े होते हुए विपक्ष की ही भाषा बोलते हुए नजर आए उन्होंने कहा की हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है वह स्वागत योग्य है इसका मतलब उन्होंने मानाणकी उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है.उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी देखा गया था कि तमाम राजनीतिक पंडित यह मान रहे थे की कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री रहते हुए हार गए तो कहीं ना कहीं पार्टी के ही भीतर घात का नतीजा था.

फिलहाल तो केशव प्रसाद मौर्य उपचुनाव को देखते हुएvबैक फुट पर नजर आ रहे हैं.ध्यान देने वाली बात यह भी है कि योगी जी के द्वारा बनाई गई विधानसभा उपचुनाव के लिए "स्पेशल 30" की टीम में उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री का नाम गायब है.अब देखना यह होगा कि 2027 चुनाव के पहले जो 10 उपचुनाव विधानसभा की सीटें हैं वह केशव प्रसाद मौर्य के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं. तो वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए भी कड़ी परीक्षा होंगी. फूलपुर से सांसद रह चुके केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा उपचुनाव में फूलपुर लोकसभा वाली में आने वाली सीट को जीतना होगा ताकि वह पार्टी में अपनी अहमियत को दिखा सकें.

राजनीतिक पंडित मानते हैं की केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दिल्ली वालों का हाथ है लेकिन देखते हैं कि हाथ कब तक रहता है और 2027 चुनाव के पहले क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी या 2027 के चुनाव तक सरकार चलेगी.वहीं समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वह कोई भी मौका नहीं छोड़ती जब वह सरकार से सवाल पूछ करके और खास तौर से जनता के बीच में यह संदेश देने की कोशिश करती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है लड़ाई कुर्सी की है जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है. 2027 चुनाव के पहले देखना यह होगा कि भाजपा उत्तर प्रदेश की आपसी लड़ाई खत्म कर पाती है या इस लड़ाई का फायदा विपक्षी दल उठाते हैं.

आजादी में ले हम सांस सभी

हरी राम यादव
बनघुसरा, अयोध्या

तिथि थी पन्द्रह माह अगस्त,
ब्रिटिश शासन का सूर्य अस्त।
जो सत्ता थी बल घमंड में मस्त,
वह हुई छिन्न-भिन्न और पस्त।

सूरज संग ले आया आजादी,
जयकार उठे जीत गयी खादी।
खुश हुई देश की पूरी आबादी,
नाचे खुशी में नाती-पोता दादी।

हवा बही धरा पर पुरवाई,
गगन में घटा बसंती छाई।
तरुवर पर आयी तरुणायी,
घर घर में बजी विजय बधाई ।

लहराया तिरंगा आसमान में,
गूंजा जन-गण-मन कान में।
हुए प्रफुल्लित जुड़े तान में,
जिनके आजादी थी जान में।

आजादी में ले हम सांस सभी,
भूलें न उनके ऋण को कभी।

क्या है सर्वाइकल पेन

ब्यूरो डेस्क

सर्वाइकल में कंधे, पीठ और गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होता है। यह लेटने या बैठने के गलत पॉश्चर के कारण या फिर ज्यादा देर तक मोबाइल चलाने से हो सकता है। जो लोग देर तक कम्प्यूटर पर काम करते है उनमें सर्वाइकल की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। यदि आप एक ही पॉश्चर में बैठकर कम्प्यूटर पर काम करें तो आपके कंधे और गर्दन के पिछले हिस्से पर दबाव पड़ता है जिससे सर्वाइकल पेन की दिक्कत हो जाती है। सर्वाइकल एक बोन का नाम है जो गर्दन के पिछले हिस्से में होती है। देर तक मोबाइल पर बात करने से भी सर्वाइकल पेन की समस्या हो सकती है। अभी हुए एक रिसर्च के अनुसार भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल पेन की समस्या सर्वाधिक पायी गयी है। 50 में से एक भारतीय महिला को सर्वाइकल की समस्या है। समस्या बढ़ने पर मरीज की मौत भी हो सकती है।

सर्वाइकल के लक्षण

गर्दन में दर्द या जकड़न, गर्दन अकड़ जाना इसके सामान्य लक्षण है। गर्दन और रीढ़ के जोड़ वाले हिस्से जिसे सर्वाइकल स्पाइन कहते है में समस्या होने पर सर्वाइकल की समस्या होती है।

सर्वाइकल पेन के कारण और बचाव

कम्प्यूटर पर लगातार काम

एक ही पॉश्चर में लगातार कम्प्यूटर पर काम करने से आपके कंधे और रीढ़ की बोन्स में दबाव पड़ता है जिससे सर्वाइकल की समस्या होती है। कम्प्यूटर पर काम करते समय आप बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। एक ही पॉश्चर में लगातार काम ना करें इससे आपको सर्वाइकल के अलावा और भी दिक्कते हो सकती हैं। काम करते समय बैठने का पॉश्चर सही होना चाहिए। सिर को एक ही दिशा में झुका कर काम ना करें इससे गर्दन और कंधे पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा और आप सर्वाइकल पेन का शिकार हो सकते हैं।

ज्यादा स्ट्रेस

ज्यादा स्ट्रेस भी सर्वाइकल पेन की वजह बन सकता है इसलिए किसी भी तरह की टेंशन या ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें अगर कोई परेशानी है तो उसका निदान करें या मनोचिकित्सक की सलाह लें।

सोने का गलत तरीका

सोने का गलत तरीका भी आपको सर्वाइकल पेन दे सकता है। इसलिए सोने का पॉश्चर सही रखें। सोते समय आरामदायक बिस्तर का चयन करें। गलत सोने का तरीका आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर गलत प्रभाव डाल सकता है।

व्यायाम

रोजाना योग और व्यायाम आपको सर्वाइकल की परेशानी से छुटकारा दिलाने में मददगार हो सकते हैं। यह आपकी इम्युनिटी को भी स्ट्रांग बनाने का बेहतर ऑप्शन हैं।

बर्फ की सिकाई

अगर आपको सर्वाइकल पेन की समस्या है और आप किसी कारणवश डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहें हैं तो बर्फ की सिकाई आपको सर्वाइकल पेन से राहत देगा। डिस्क्लेमर: इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी बीमारी के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ■

एलोवेरा फेस पैक

ब्यूरो डेस्क

जब ठंड का मौसम होता है तो स्किन को अतिरिक्त केयर की जरूरत होती है ताकि स्किन अधिक स्मूद नजर आए। इस मौसम में स्किन का ख्याल रखने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करना काफी अच्छा माना जाता है। दरअसल, एलोवेरा स्किन की कई तरह की प्रॉब्लम्स को नेचुरल तरीके से दूर कर सकता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको एलोवेरा की मदद से बनने वाले कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप विंटर में आसानी से बनाकर अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं-

आवश्यक सामग्री-

- दो बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

- एक चम्मच शहद

- एक चम्मच रोज वाटर

फेस पैक बनाने का तरीका-

- फेस पैक बनाने के लिए आप सबसे पहले एलोवेरा का पत्ता तोड़कर उसका जेल निकाल लें।

- अब आप इस जेल में शहद व रोज वाटर मिक्स करें।

- इसके बाद आप अपने फेस को क्लीन करके इस पैक को चेहरे पर लगाएं और बेहद हल्के हाथों से मसाज करें।

- करीबन 10 मिनट बाद गुनगुने पानी की मदद से फेस वॉश करें।

एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल से बनाएं फेस पैक

अगर आपकी स्किन बहुत अधिक ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है तो ऐसे में आप इस फेस पैक को बना सकती हैं।

आवश्यक सामग्री-

- 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

- 1 बड़ा चम्मच रोज वाटर

- 2-3 बूंद टी ट्री ऑयल

इस्तेमाल करने का तरीका-

- सबसे पहले आप एलोवेरा के पत्ते को तोड़कर उसका जेल निकाल लें।

- अब आप इस जेल में रोज वाटर और 2-3 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाएं।

- अब आप इसे पैक को अपने चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं और फिर इसे धो लें।

- आप सप्ताह में एक से दो बार इस फेस पैक को लगा सकते हैं।

एलोवेरा और विटामिन ई से बनाएं फेस पैक

अगर आपकी स्किन को विंटर में डीप नरिश्मेंट देना चाहती हैं तो ऐसे में एलोवेरा जेल को विटामिन ई ऑयल कैप्सूल को मिक्स करें।

आवश्यक सामग्री-

- 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

- एक विटामिन ई कैप्सूल

इस्तेमाल करने का तरीका-

- सबसे पहले एलोवेरा के पत्ते को तोड़कर उसका जेल निकाल लें।

- इसके बाद आप बाउल में विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल मिक्स करें।

- अब आप अपने चेहरे को वॉश करें और इस पैक को लगाएं।

- करीबन दस मिनट बाद आप अपने चेहरे को पानी की मदद से वॉश करें। ■

सभी प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
15 अगस्त
कमल रुकेंगी नही,
कलम झुकेगी नही !!
सच को उठाएंगे ,
झूठ को गिराएंगे ।
धर्म को छोड़कर ,
देश को बचाएंगे ।।
एकता बनाएंगे,
अनेकता को मिटाएंगे।
बाकी रंग छोड़कर,
तिरंगा फहराएंगे ।।
बधाईना पूछो जमाने से की
हमारी क्या कहानी है ii
हमारी तो बस इतनी सी पहचान है
कि हम हिंदुस्तानी हैं
रामू गौड़ (ब्यूरो चीफ) सिद्धार्थनगर
ग्राम प्रधान बैदौली निवासी लाड़ील
शुभम ग्राफिक्स
पत्रिका कम्पोजिंग एवं डिजाईनिंग तथा
विज्ञापन बनवाने के लिए संपर्क करें
Hazratganj, Lucknow
तेजस बिन्दु
तेजस बिन्दु
शुभम-8881544447
yshubham2024@gmail.com

मुलायम आर्मी
भारत एकता मिशन
स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाएं
संस्थापक
कालीचरन यादव
(राष्ट्रीय सचिव मुलायम आर्मी)
भारत एकता मिशन